International Journal of Enhanced Research in Educational Development (IJERED)
ISSN: 2320-8708, Volume 14, Issue 2, March-April

पितृसत्तात्मक संरचना और महिलाओं की निर्णय क्षमताः ग्रामीण एवं शहरी परिप्रेक्ष्य में एक तुलनात्मक अध्ययन

डॉ. राहुल

शोधार्थी (डॉक्टर ऑफ लिटरेचर) समाजकार्य-समाजशास्त्र विभाग, महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखण्ड, विश्वविद्यालय, बरेली (उत्तर प्रदेश)

सार

यह शोध पत्र पितृसत्तात्मक सामाजिक संरचना के भीतर महिलाओं की स्वायत्तता और उनकी निर्णय लेने की क्षमता का एक तुलनात्मक विश्लेषण प्रस्तुत करता है। अध्ययन का मुख्य उद्देश्य यह समझना है कि ग्रामीण और शहरी वातावरण में सांस्कृतिक मानदंड, आर्थिक संसाधन और सामाजिक-आर्थिक स्थिति महिलाओं की घरेलू और व्यक्तिगत निर्णय प्रक्रिया को किस प्रकार प्रभावित करती है। अध्ययन के निष्कर्षों से संकेत मिलता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में निर्णय क्षमता अक्सर भूमि स्वामित्व और कृषि गतिविधियों में भागीदारी से जुड़ी होती है, फिर भी पितृसत्तात्मक बाधाएं स्वास्थ्य सेवाओं और वित्तीय स्वायत्तता तक उनकी पहुँच को सीमित करती हैं। इसके विपरीत, शहरी क्षेत्रों में शिक्षा और डिजिटल साक्षरता ने महिलाओं की भूमिका में सुधार किया है, लेकिन सामाजिक-सांस्कृतिक कारक अभी भी पूर्ण समानता के मार्ग में बाधा बने हुए हैं। यह शोध स्पष्ट करता है कि केवल वित्तीय पहुँच ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि संस्थागत और सामाजिक परिवर्तनों के माध्यम से महिलाओं की 'एजेंसी' को मजबूत करना अनिवार्य है। यह अध्ययन नीति निर्माताओं को यह सुझाव देता है कि ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए लैंगिक समानता की दिशा में लक्षित हस्तक्षेप आवश्यक हैं।

महत्वपूर्ण शब्द- पितृसत्ता, निर्णय क्षमता, महिला सशक्तिकरण, ग्रामीण-शहरी तुलना, सामाजिक-आर्थिक स्थिति, स्वायत्तता।

---

1. परिचय

परिवार में महिलाओं की भूमिका ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और सामाजिक-आर्थिक वजहों से बहुत ज्यादा बनी है। पारंपरिक रूप से महिलाओं की भूमिकाएँ परिवार के ढाँचे और समाज की उम्मीदों से बहुत करीब से जुड़ी होती थीं। पुराने और मध्यकालीन भारत में परिवार ज्यादातर संयुक्त परिवार थे जहाँ महिलाओं से घर चलाने वाली, देखभाल करने वाली और माँ की भूमिकाएँ निभाने की उम्मीद की जाती थी। हालाँकि जैसे-जैसे समय के साथ परिवार का ढाँचा बदला धीरे-धीरे सांझा परिवारों की तरफ बदलाव आया परिवार में महिलाओं की भूमिका में भी बड़े बदलाव आए। यह भाग पारंपरिक संयुक्त परिवार से लेकर परमाणु परिवारों की तरफ आज के बदलाव तक परिवार के ढाँचे में महिलाओं की भूमिका के ऐतिहासिक नजरिए को देखता है।

1.1 पारंपरिक पारिवारिक संरचना और महिलाओं की भूमिकाएँ

भारतीय समाज में पारंपरिक पारिवारिक संरचना मुख्यतः पितृसत्तात्मक रही है। परिवार का नेतृत्व सामान्यतः पुरुष करता था और अधिकांश निर्णय उसी के हाथ में होते थे। उस समय परिवार प्रायः संयुक्त परिवार प्रणाली पर आधारित होते थे इस प्रणाली में कई पीढ़ियाँ दादा-दादी, माता-पिता, बच्चे, चाचा, चाची और चचेरे भाई-बहन एक ही छत के नीचे प्रायः एक बड़े घर में एक साथ रहते थे। संयुक्त परिवार प्रणाली को मिलकर रहने, साझा जिम्मेदारियों और मिलकर फैसले लेने को बढ़ावा देने के तरीके के तौर पर देखा जाता था।

इन बड़े परिवारों में महिलाओं की भूमिका पारंपरिक रूप से गृहणी , माँ और देखभाल करने वाली की उम्मीदों से तय होती थी । वे मुख्य रूप से घर संभालने, बच्चों की परवरिश करने और परिवार के सदस्यों की भावनात्मक और शारीरिक जरूरतों का ध्यान रखने के लिए जिम्मेदार थीं। परिवार में, घर के मूल्यों, विश्वासों और रोजाना के कामकाज को बनाने में माँ की भूमिका बहुत जरूरी थी। महिलाओं से उम्मीद की जाती थी कि वे परिवार का आदेश बनाए रखें यह पक्का करें कि बच्चों की ठीक से देखभाल हो और परिवार की परंपराओं और रीति-रिवाजों को बनाए रखा जाए।

महिलाएँ, परिवार के कामकाज के लिए जरूरी होने के बावजूद जरूरी फैसलों में उनकी बात नहीं मानी जाती थी और उनकी आजादी प्रायः पुरुष-प्रधान नियमों से रुकी रहती थी। उनका मुख्य कार्य परिवार की जिम्मेदारियों को पूरा करने और घर में तालमेल बनाए रखने पर रहता था।

अपनी घरेलू जिम्मेदारियों के अतिरिक्त , संयुक्त परिवार में महिलाओं को अक्सर कठिन सामाजिक पदानुक्रम से भी निपटना पड़ता था। परिवार में बुजुर्ग महिलाएँ, विशेषकर सास, छोटी महिलाओं पर अत्यधिक प्रभाव रखती थीं। वे परिवार की परंपराओं और नियमों का पालन कराने में निर्णायक भूमिका निभाती थीं। उनके व्यवहार, घरेलू कामों और परिवार के अंदर बातचीत को तय करती थीं। इस पदानुक्रमिक ने महिलाओं की व्यक्तिगत आजादी और स्वायत्तता को कम कर दिया जिससे पारंपरिक लिंग भूमिका और मजबूत हुए (डिक्सन, 2013)।

20वीं सदी के बीच में भारत में बड़े सामाजिक और आर्थिक बदलाव होने लगे जिससे संयुक्त परिवार प्रणाली खत्म होने लगा और एकल परिवार का संरचना बढ़ने लगा। यह बदलाव शहरीकरण, प्रवासन, आधुनिकरण और बदलते आर्थिक हालात जैसे कारणों से हुआ। जैसे-जैसे परिवार बेहतर नौकरी और पढ़ाई के मौकों के लिए शहरों में जाने लगे संयुक्त परिवार प्रणाली धीरे-धीरे टूटने लगी और कई परिवारों ने एकल परिवार मॉडल अपना लिया जहाँ सिर्फ माता-पिता और उनके बच्चे ही साथ रहते हैं।

एकल परिवार की तरफ इस बदलाव से परिवार में महिलाओं की भूमिका में बहुत बदलाव आए। जिम्मेदारियाँ बांटने के लिए परिवार के कम सदस्य होने से घर में महिलाओं की भूमिका बदल गई। एकल परिवार में महिलाओं को प्रायः घर के काम संभालने में आजादी मिलती थी क्योंकि वे अब सास या दूसरे बड़े रिश्तेदारों जैसे परिवार के बड़े सदस्यों के नियंत्रण में नहीं रहती थीं। इससे महिलाओं को घर के फैसले लेने, पैसे प्रबंधित करने और परिवार में काम के बँटवारे पर बातचीत करने में ज्यादा सक्रिय भूमिका निभाने का मौका मिला।

इसके अतिरिक्त एकल परिवार में बदलाव से महिलाओं को घर के बाहर आजादी से पढ़ाई और व्यवसायिक जीवन बनाने का मौका मिला जिससे उनकी आर्थिक आजादी बढ़ी । इस व्यवस्था में महिलाओं ने प्रायः परिवार के फैसले लेने में मिलकर काम करने वाली भूमिका निभाई जिसमें दोनों साझेदार पति और पत्नी, पैसे, बच्चों की पढ़ाई और करियर के चुनाव से जुड़ी जिम्मेदारियाँ शेयर करते थे। यह बदलाव खास तौर पर शहरी इलाकों में साफ दिखा जहाँ महिलाओं ने बड़ी संख्या में कार्यबल में हिस्सा लेना शुरू कर दिया जिससे घर की आमदनी और आर्थिक योजना बनाना में मदद मिली (शुक्ला एट अल., 2025)।

एकल परिवार प्रणाली ने घर के अंदर बराबरी वाले रिश्ते बनाए । छोटे परिवार में महिलाओं का अपने समय, अपनी भूमिकाओं और परिवार के अंदर अपनी बातचीत पर ज्यादा नियंत्रण होता था। इस बदलाव ने महिलाओं को व्यक्तिगत और पारिवारिक फैसले लेने में आजादी दी जिससे वे घर के अंदर अपनी भूमिकाओं को ज्यादा प्रभावदार तरीके से निभा पाईं। जबकि पारंपरिक लैंगिक भूमिका कुछ हद तक बने रहे एकल परिवार के संरचना ने महिलाओं को अपनी बात कहने और मजबूती पाने के ज्यादा मौके दिए विशेषकर जब संयुक्त परिवारकी सख्त पदानुक्रमिक से तुलना की गई (टेसेमा एट अल., 2025)।

जैसे-जैसे महिलाओं ने पारंपरिक घरेलू दायरे से बाहर नई भूमिकाएँ निभानी शुरू कीं उन्हें अपने परिवार के आर्थिक फैसलों में भी मजबूत आवाज मिली । कई महिलाएँ नौकरी या उद्यमिता के जरिए आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो गईं जिससे वे निवेश, बचत और घर के खर्चों से जुड़े फैसलों में ज्यादा सक्रिय रूप से हिस्सा ले पाईं। महिलाओं के स्वयं सहायता समूह और छोटे व्यवसाय के बढ़ने से परिवार के अंदर आर्थिक फैसले लेने में उनकी भूमिका और बढ़ गई जिससे महिलाओं को न केवल परिवार के आर्थिक सहायता करने का मौका मिला बल्कि वे अपने समुदायों में नेतृत्व की भूमिका भी निभा सकीं (अली और कामराजू , 2023)।

इस नए पारिवारिक संरचना ने महिलाओं के लिए अपने अधिकारों के लिए ज्यादा प्रभावदार तरीके से आवाज उठाने का रास्ता भी खोला। एकल परिवार में महिलाओं के पास पारंपरिक नियमों को चुनौती देने और शादी, पितृत्व और सामाजिक भूमिका में बराबरी पाने के लिए जगह थी। नतीजतन महिलाओं के अधिकारों के लिए आंदोलन जोर पकड़ने लगे जो पारिवारिक कानूनों में बदलाव की वकालत करने लगे जैसे कि हिंदू विवाह अधिनियम और घरेलू हिसां अधिनियिम जो परिवार के अंदर महिलाओं को कानूनी सुरक्षा देते थे (कोचर एट अल., 2022)।

भारत में संयुक्त परिवारप्रणाली से एकल परिवार संरचना में बदलाव का परिवार में महिलाओं की भूमिका पर गहरा प्रभाव पड़ा है। जहाँ संयुक्त परिवार प्रणाली में प्रायः महिलाओं को पारंपरिक और अधीनस्थ भूमिकाएँ दी जाती थीं वहीं छोटे परिवार की ओर बदलाव ने महिलाओं को परिवार के फैसले लेने में ज्यादा आजादी और भागीदारी दी है।

रोजगार और उद्यमिता दोनों के जरिए महिलाओं की आर्थिक भागीदारी में बढ़ोतरी महिलाओं की भूमिकाओं में सबसे बड़े बदलावों में से एक रही है जिससे आर्थिक आजादी और सामाजिक गतिशीलता बढ़ी है। हालाँकि चुनौतियाँ बनी हुई हैं विशेषकर ग्रामीण इलाकों और रूढ़िवादी परिवारों में, परिवार संरचना के विकास ने परिवार में लैंगिक भूमिकाओं के लिए ज्यादा बराबरी वाला नजरिया अपनाने का रास्ता बनाया है।

2. साहित्य का पुनर्वालोकन

वादेई, वादेई और बोनुएडी (2025) ने घाना के ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में महिलाओं की नौकरी व पारिवारिक फैसलों में भूमिका की गतिविधियों का विश्लेषण किया। शोध से उजागर हुआ कि सशुल्क रोजगारों में महिलाओं की वृद्धि ने घरेलू निर्णय शक्ति को विशेषतः शहरी भागों में मजबूत किया।

टेसेमा एट अल. (2025) ने दक्षिणी इथियोपिया के ग्रामीण भागों में बाल पोषण फैसलों पर सामाजिक-सांस्कृतिक रुकावटों की पड़ताल की। निष्कर्षों से पता चला कि बाल पोषण चुनाव सांस्कृतिक धारणाएँ व लिंग मानदंडों से बंधे रहते हैं, जिससे महिलाओं को संतान स्वास्थ्य फैसलों में सीमित आजादी मिलती है।

शुक्ला एट अल. (2025) ने भारत में कृषि कार्यों में खेत मजूर महिलाओं की निर्णय शक्ति प्रभावित करने वाले कारकों की जाँच की। अध्ययन से सामने आया कि महिलाओं की फैसला क्षमता संसाधन सुगमता, साक्षरता व परिवार पुरुषों की सहायता पर आश्रित है।

सोह एट अल. (2024) ने कैमरून के ग्रामीण घरों में महिलाओं की फैसला शक्ति के परिवार पोषण गुणवत्ता व आय व्यय पर प्रभाव की खोज की। शोध से सामने आया कि आय पर महिलाओं का मजबूत नियंत्रण भोजन, चिकित्सा व शिक्षा खर्च को प्राथमिक बनाता है, जिससे पारिवारिक पोषण उन्नत होता है।

ली (2022) ने पारिवारिक फैसला शक्ति के महिलाओं की प्रसन्नता व जीवन परितोष पर असर की जाँच की। अध्ययन से पता चला कि वित्त व संतान देखभाल फैसलों में प्रभावी महिलाएँ अधिक आनंदित व जीवन से संतुष्ट रहती हैं।

झेंग और लू (2021) ने चीन के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रवासी पुरुषों के अभाव वाली महिलाओं की फैसला लेने की योग्यता पर सूचना-संवाद तकनीक (आईसीटी) के असर का मूल्यांकन किया। शोध से सामने आया कि मोबाइल फोन व इंटरनेट जैसी आईसीटी ने महिलाओं को पारिवारिक चुनावों-खासकर वित्तीय व सामाजिक मामलों में-अधिक भागीदारी प्रदान की। आईसीटी ने ज्ञान उपलब्धता, एकांतता न्यूनीकरण व दूरस्थ परिवारजनों से संपर्क सुधारकर उन्हें सशक्त बनाया।

लेकोटेरे और वुइट्स (2021) ने कृषक परिवारों में सहभागी फैसला तंत्रों के महिलाओं के उत्थान पर प्रभाव की खोज की। निष्कर्षों से पुष्टि हुई कि ये मॉडल महिलाओं को पारिवारिक मुद्दों पर मत व्यक्त करने की छूट देते हैं, हालाँकि पुरुषप्रधान ढाँचा उनके प्रभाव को बाधित रखता है।

वैन ट्रुओंगा एट अल. (2020) ने ग्रामीण वियतनाम में पारिवारिक फैसला प्रक्रिया में लिंग भूमिकाओं का विश्लेषण कर पुरुष-महिला सहभागिता भिन्नताओं की पड़ताल की। अध्ययन से ज्ञात हुआ कि महिलाएँ दैनिक घरेलू कार्य व लघु व्यय प्रबंधन संभालती हैं, लेकिन प्रमुख वित्तीय व सामाजिक फैसलों का अंतिम अधिकार पुरुषों के पास रहता है।

अकोस्टा एट अल. (2020) ने कृषक परिवारों में 'सहभागी फैसला तंत्र' की अवधारणा पर शोध किया, जिसमें पुरुष-महिला फैसला विभाजन का मूल्यांकन किया गया। निष्कर्षों से ज्ञात हुआ कि भले औपचारिक रूप से संयुक्त चुनाव होते हों, महिलाओं का वास्तविक प्रभाव सामाजिक-सांस्कृतिक कारक व संसाधन असमानता से सीमित रहता है।

विलियम्स (2019) ने ग्रामीण जावा में विकास, जनसांख्यिकीय परिवर्तन व पारिवारिक फैसलों के मध्य संबंध की खोज की। शोध ने जनसांख्यिकीय बदलाव व विकास योजनाओं के महिलाओं की पारिवारिक भूमिका पर प्रभाव का विश्लेषण किया। अध्ययन से उजागर हुआ कि ग्रामीण जावा में महिलाएँ घरेलू प्रबंधन का प्रमुख भार उठाती हैं, लेकिन पुरानी लिंग भूमिकाएँ व आर्थिक निर्भरता उनकी निर्णय शक्ति को बाँधे रखती हैं।

बेस्चर-डोनेली और स्मिथ (2019) ने ग्रामीण महिलाओं की विकसित भूमिकाओं व सामाजिक स्थान का परीक्षण किया, विशेषतः पारिवारिक फैसलों में उनके प्रभाव के परिप्रेक्ष्य से। अध्याय ने कृषि, घरेलू संचालन व समुदाय नेतृत्व में महिलाओं की भूमिकाओं के कालान्तरिक परिवर्तन को व्यापक सामाजिक-आर्थिक-राजनीतिक बदलावों से जोड़ा।

टाडेले, टेसफे और केबेडे (2019) ने इथियोपिया के ग्रामीण भागों में प्रजनन स्वास्थ्य-अधिकार फैसलों पर महिलाओं की निर्णय क्षमता को आकार देने वाले साधनों की खोज की। परिणामों से ज्ञात हुआ कि प्रजनन चुनावों में स्वतंत्रता साक्षरता, आय व सामाजिक धारणाओं से बंधी रहती है।

प्रशांति और देवी (2019) ने भारत के ग्रामीण इलाकों में महिलाओं हेतु जीवन कौशल-निर्णय, समस्या निवारण व संपर्क क्षमता-मजबूत करने वाले हस्तक्षेप के प्रभाव का मूल्यांकन किया। शोध से प्रमाणित हुआ कि इस प्रयास ने महिलाओं की चयन शक्ति को सकारात्मक रूप से प्रभावित किया, जिससे वे पारिवारिक व सामुदायिक चयनों में सक्रिय हो गईं।

अख्तर एट अल. (2018) ने दक्षिणी पंजाब के ग्रामीण पंजाब में सामाजिक व कृषि चुनावों में महिलाओं के योगदान का आकलन किया। विश्लेषण से सामने आया कि कृषि अभियानों में भाग लेने वाली महिलाएँ भूमि प्रबंधन, धन संबंधी व फसल चयन निर्णयों में मामूली भूमिका निभाती हैं।

अबरार-उल-हक, जाली और इस्लाम (2017) ने पाकिस्तान के ग्रामीण महिलाओं में निर्णय शक्ति व सशक्तीकरण के मध्य संबंध की खोज की। निष्कर्षों से स्पष्ट हुआ कि घरेलू धन, स्वास्थ्य व जीविका चयनों में स्वतंत्रता वाली महिलाएँ उच्च सशक्तीकरण स्तर प्राप्त करती हैं। अध्ययन ने शिक्षा, आर्थिक साधनों सुगमता व सहायता जाल को निर्णय क्षमता उन्नयन के लिए निर्णायक ठहराया।

2.1 अनुसंधान अंतराल

- ग्रामीण इलाकों में लैंगिक भेदभाव को समाप्त करने और महिलाओं को सशक्त बनाने में कानूनी और संस्थागत संरचनाओं की भूमिका पर अधिक शोध की आवश्यकता है।
- वैश्वीकरण का ग्रामीण महिलाओं की भूमिका और परिवार के निर्णय लेने पर प्रभाव विशेषकर नए आर्थिक अवसरों और चुनौतियों के संदर्भ में अध्ययन किया जाना चाहिए।
- पारिवारिक संरचना में बदलाव, जैसे संयुक्त परिवार से एकल परिवार की ओर बदलाव, और महिलाओं के निर्णय लेने की बढ़ती क्षमता के बीच संबंध का विश्लेषण करना चाहिए।
- ग्रामीण परिवारों में काम के लैंगिक विभाजन और इसके घरेलू एवं आर्थिक क्षेत्रों में महिलाओं की स्वतंत्रता और निर्णय लेने पर प्रभाव का अध्ययन करना चाहिए।

3. शोध प्रविधि

3.1 शोध का प्रारूप

यह शोध वर्णनात्मक और विश्लेषणात्मक प्रकृति का है। इसमें हरियाणा के ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की वर्तमान स्थिति का वर्णन करने के साथ-साथ उन कारकों का विश्लेषण किया गया है जो उनकी निर्णय लेने की शक्ति को प्रभावित करते हैं।

3.2 प्रतिदर्श चयन (नमूनाकरण)

विधि- इस अध्ययन के लिए स्तरीकृत यादृच्छिक प्रतिचयन विधि का प्रयोग किया गया है।
क्षेत्र- शोध कार्य हरियाणा के ग्रामीण अंचल में संपन्न हुआ है।
प्रतिदर्श आकार- कुल ५०० उत्तरदाताओं (महिलाओं) का चयन किया गया है ताकि परिणाम पूरे क्षेत्र का सटीक प्रतिनिधित्व कर सकें।

3.3 आंकड़ों का संग्रह

शोध में प्राथमिक और द्वितीयक दोनों प्रकार के आंकड़ों का उपयोग किया गया है -
प्राथमिक आंकड़े - सूचनाएं एकत्रित करने के लिए एक संरचित प्रश्नावली और साक्षात्कार अनुसूची तैयार की गई। इसमें मुख्य रूप से चार खंड शामिल किए गएः

1. पारिवारिक निर्णयों में भागीदारी।
2. सामाजिक-आर्थिक स्थिति।
3. सांस्कृतिक और पारंपरिक बाधाएं।

द्वितीयक आंकड़े- पूर्व प्रकाशित शोध पत्र, सरकारी रिपोर्ट (जैसे जनगणना और स्वास्थ्य सर्वेक्षण), पुस्तकें और पत्रिकाओं से संदर्भ लिए गए हैं।

3.4 शोध के चर

अध्ययन में निम्नलिखित चरों पर गहन विचार किया गया है-
स्वतंत्र चर- सामाजिक-सांस्कृतिक कारक, आर्थिक स्थिति, शिक्षा का स्तर और सरकारी नीतियां।
आश्रित चर- परिवार के भीतर निर्णय लेने की क्षमता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता।

3.5 प्रारंभिक परीक्षण (पायलट अध्ययन)

प्रश्नावली की प्रभावशीलता और भाषा की स्पष्टता की जांच करने के लिए मुख्य सर्वेक्षण से पहले ३० उत्तरदाताओं पर एक प्रारंभिक परीक्षण किया गया। विशेषज्ञों के सुझावों के आधार पर प्रश्नावली में आवश्यक सुधार किए गए ताकि आंकड़ों की विश्वसनीयता बनी रहे।

3.6 आंकड़ों का विश्लेषण

एकत्रित आंकड़ों का विश्लेषण करने के लिए विभिन्न सांख्यिकीय विधियों का प्रयोग किया गया है -

- प्रतिशत और औसत- सामान्य रुझानों को समझने के लिए।

- सारणीकरण और चित्रण- परिणामों को स्पष्ट रूप से दर्शाने के लिए तालिकाओं, बार चार्ट और रेखाचित्रों का उपयोग किया गया है।

4. आंकड़ा विश्लेषण
इस शोध कार्य में महिलाओं के फैसला-लेने की क्षमता में प्रमुख चुनौतियों का परीक्षण प्रस्तुत किया गया है। इन्हें सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक तथा विधिक कारकों के रूप में चिह्नित किया गया है, जो उनकी सहभागिता को सीमित रखते हैं। अध्ययन का उद्देश्य उन तत्वों की पहचान करना है जो महिलाओं की भूमिका प्रभावित करते हैं तथा उनकी स्थिति उन्नत करने हेतु संभावित उपाय सुझाना है। महिलाओं का सशक्तिकरण एवं लिंग समानता को प्रोत्साहन देने के लिए इन अवरोधों की पहचान और निवारण सर्वोपरि आवश्यक है।

4.1 सामाजिक और सांस्कृतिक बाधाएँ

तालिका 4.1: क्या सामाजिक मान्यताएँ निर्णय लेने में बाधाएँ डालती हैं?

प्रतिक्रियाएँ	आवृत्ति	प्रतिशत	कुल प्रतिशत
मजबूत बाधाएँ	118	23.6%	23.6%
कुछ बाधाएँ	162	32.4%	56.0%
सामान्य	124	24.8%	80.8%
कम बाधाएँ	65	13.0%	93.8%
कोई बाधा नहीं	31	6.2%	100.0%
कुल	**500**	**100%**	**100%**

सांख्यिकीय चित्र 4.1: क्या सामाजिक मान्यताएँ निर्णय लेने में बाधाएँ डालती हैं?
23.6 प्रतिशत उत्तरदाताओं को लगता है कि सामाजिक मानदंड फैसलों में बड़ी रुकावट पैदा करते हैं, जबकि 32.4 प्रतिशत इन्हें सीमित बाधा मानते हैं। 24.8 प्रतिशत के विचार में ये सामान्य असर डालते हैं और 13 प्रतिशत को न्यूनतम प्रभाव नजर आता है।

International Journal of Enhanced Research in Educational Development (IJERED)
ISSN: 2320-8708, Volume 14, Issue 2, March-April

महज 6.2 प्रतिशत ही इन्हें बिल्कुल अनुपस्थित पाते हैं। ये आंकड़े प्रमाणित करते हैं कि बहुसंख्यक लोग महिलाओं के निर्णय लेने में सामाजिक धारणाओं को महत्वपूर्ण अवसर के रूप में स्वीकारते हैं।

तालिका 4.2: क्या संसाधनों की कमी के कारण पारिवारिक निर्णयों में भागीदारी सीमित होती है?

प्रतिक्रियाएँ	आवृत्ति	प्रतिशत	कुल प्रतिशत
पूरी तरह से सीमित	124	24.8%	24.8%
कुछ हद तक सीमित	153	30.6%	55.4%
सामान्य	127	25.4%	80.8%
सीमित नहीं	69	13.8%	94.6%
कोई नहीं	27	5.4%	100.0%
कुल	**500**	**100%**	**100%**

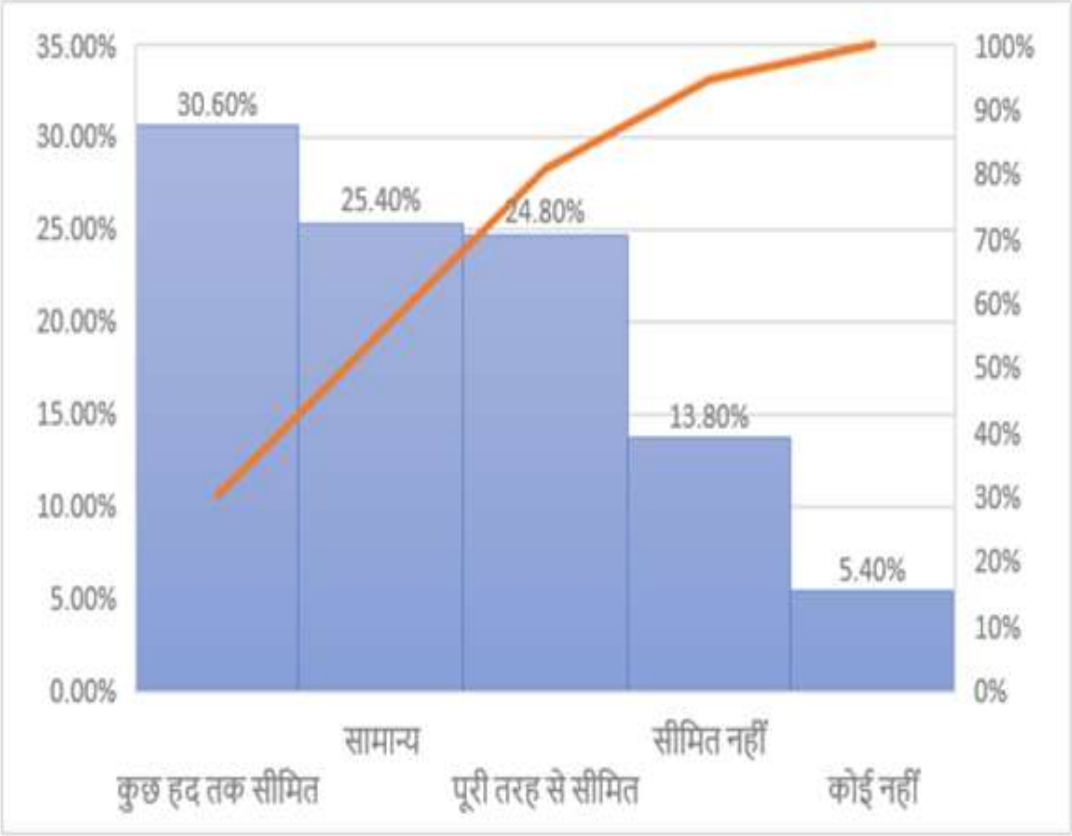

सांख्यिकीय चित्र 4.2: क्या संसाधनों की कमी के कारण पारिवारिक निर्णयों में भागीदारी सीमित होती है?

24.8 प्रतिशत का मत है कि संसाधनों की कमी महिलाओं की भागीदारी को पूरी तरह अवरुद्ध कर देती है, जबकि 30.6 प्रतिशत का कहना है कि यह कुछ हद तक बाधा बनती है। 25.4 प्रतिशत लोगों को लगता है कि संसाधन अभाव का प्रभाव सामान्य स्तर का है और 13.8 प्रतिशत के अनुसार इसका कोई खास असर नहीं पड़ता। मात्र 5.4 प्रतिशत ही मानते हैं कि संसाधनों की कमी से कोई समस्या उत्पन्न ही नहीं होती।

International Journal of Enhanced Research in Educational Development (IJERED)
ISSN: 2320-8708, Volume 14, Issue 2, March-April

तालिका 4.3: क्या पितृसत्तात्मक विचारधारा निर्णय लेने की क्षमता को रोकती है?

प्रतिक्रियाएँ	आवृत्ति	प्रतिशत	कुल प्रतिशत
पूरी तरह से रोकती है	135	27.0%	27.0%
कुछ हद तक रोकती है	146	29.2%	56.2%
सामान्य	114	22.8%	79.0%
रोकती नहीं	67	13.4%	92.4%
कोई प्रभाव नहीं	38	7.6%	100.0%
कुल	**500**	**100%**	**100%**

सांख्यिकीय चित्र 4.3: क्या पितृसत्तात्मक विचारधारा निर्णय लेने की क्षमता को रोकती है?
27 प्रतिशत लोगों का विचार है कि यह पूरी तरह बाधित कर देती है, 29.2 प्रतिशत के अनुसार यह आंशिक रूप से रोकावट पैदा करती है, 22.8 प्रतिशत को इसका मध्यम प्रभाव दिखता है, 13.4 प्रतिशत मानते हैं कि यह कोई अवरोध नहीं बनाती और 7.6 प्रतिशत ही इसे प्रभावहीन बताते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि पितृसत्तात्मक मान्यताओं को महिलाओं की फैसला लेने की क्षमता में प्रमुख चुनौती के रूप में स्वीकृत किया जा रहा है।

तालिका 4.4: क्या कानूनी बाधाएँ महिलाओं को निर्णय लेने में समान रूप से भाग लेने से रोकती हैं?

प्रतिक्रियाएँ	आवृत्ति	प्रतिशत	कुल प्रतिशत
पूरी तरह से रोकती हैं	116	23.2%	23.2%
कुछ हद तक रोकती हैं	157	31.4%	54.6%
कोई रोक नहीं	153	30.6%	85.2%
रोकती नहीं	74	14.8%	100.0%
कुल	**500**	**100%**	**100%**

सांख्यिकीय चित्र 4.4: क्या कानूनी बाधाएँ महिलाओं को निर्णय लेने में समान रूप से भाग लेने से रोकती हैं?
23.2 प्रतिशत लोग मानते हैं कि कानूनी रुकावटें महिलाओं को निर्णय प्रक्रिया में बराबरी से शामिल होने से पूरी तरह वर्जित कर देती हैं, जबकि 31.4 प्रतिशत इन्हें सीमित अवसर मानते हैं, 30.6 प्रतिशत के विचार में ये कोई बाधा नहीं बनातीं। इसके अतिरिक्त 14.8 प्रतिशत भी इन्हें फैसलों में प्रभावरहित बताते हैं। यह दर्शाता है कि विधिक बाधाएँ महिलाओं की सक्रियता को आंशिक रूप से प्रभावित तो करती हैं, मगर पूर्णतः प्रतिबंधित नहीं रखतीं।

तालिका 4.5: क्या परिवार महत्वपूर्ण निर्णयों में भागीदारी को समर्थन नहीं करता?

प्रतिक्रियाएँ	आवृत्ति	प्रतिशत	कुल प्रतिशत
पूरी तरह से समर्थन नहीं	135	27.0%	27.0%
कुछ हद तक समर्थन नहीं	147	29.4%	56.4%
सामान्य	138	27.6%	84.0%
समर्थन करता है	80	16.0%	100.0%
कुल	500	100%	100%

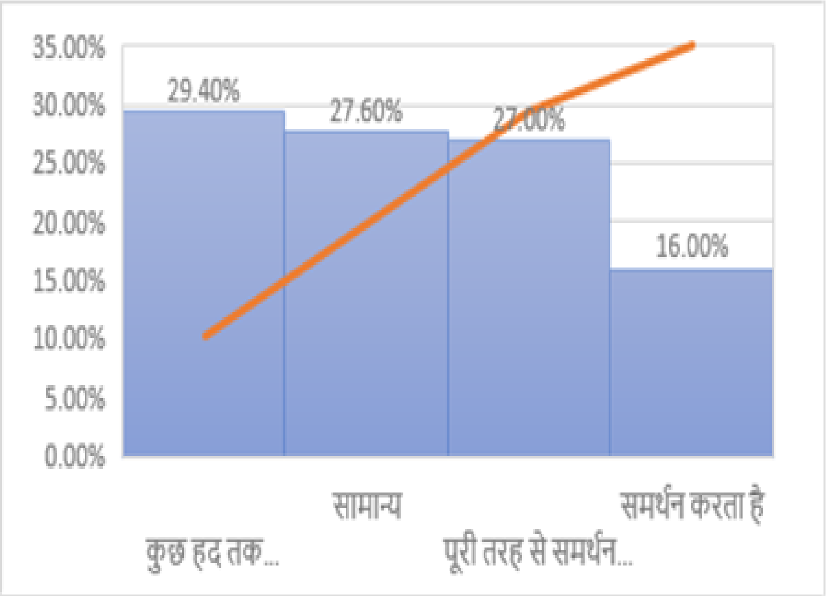

सांख्यिकीय चित्र 4.5: क्या परिवार महत्वपूर्ण निर्णयों में भागीदारी को समर्थन नहीं करता?
27 प्रतिशत के अनुसार परिवार महत्वपूर्ण फैसलों में महिलाओं की सहभागिता को पूर्णतः प्रोत्साहित नहीं करता, जबकि 29.4 प्रतिशत इसे आंशिक असमर्थन मानते हैं। 27.6 प्रतिशत को यह स्थिति सामान्य लगती है और केवल 16 प्रतिशत ही परिवार को

सहयोगी पाते हैं। इससे पता चलता है कि ज्यादातर परिवारों में महिलाओं को प्रमुख निर्णयों की प्रक्रिया में सीमित प्रोत्साहन ही प्राप्त होता है।

4.2 आर्थिक और शैक्षिक बाधाएँ

तालिका 4.6: क्या महिलाओं को ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी क्षेत्रों की तुलना में अधिक भेदभाव का सामना करना पड़ता है?

प्रतिक्रियाएँ	आवृत्ति	प्रतिशत	कुल प्रतिशत
पूरी तरह से सहमत	142	28.4%	28.4%
सहमत	157	31.4%	59.8%
नपे-तुले	118	23.6%	83.4%
असहमत	65	13.0%	96.4%
पूरी तरह से असहमत	18	3.6%	100%
कुल	**500**	**100%**	**100%**

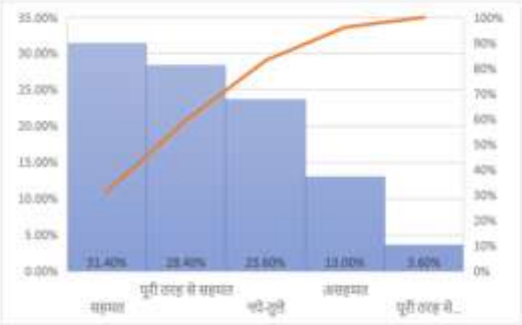

सांख्यिकीय चित्र 4.6 क्या महिलाओं को ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी क्षेत्रों की तुलना में अधिक भेदभाव का सामना करना पड़ता है? 28.4 प्रतिशत महिलाएँ पूरी तरह मानती हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी इलाकों से अधिक भेदभाव झेलना पड़ता है, 31.4 प्रतिशत कुछ हद तक सहमत हैं, 23.6 प्रतिशत उदासीन हैं, और 13 प्रतिशत इसका विरोध करती हैं। केवल 3.6 प्रतिशत ही स्पष्ट रूप से अस्वीकार करती हैं। यह आंकड़े प्रमाणित करते हैं कि बहुमत महिलाएँ ग्रामीण स्थानों पर शहरी की अपेक्षा कठोर पक्षपात का अनुभव करती हैं।

तालिका 4.7: क्या पारंपरिक मान्यताओं के कारण कुछ पारिवारिक निर्णयों से महिलाएँ बाहर होती हैं?

प्रतिक्रियाएँ	आवृत्ति	प्रतिशत	कुल प्रतिशत
हमेशा बाहर होती हैं	138	27.6%	27.6%
कभी कभी बाहर होती हैं	158	31.6%	59.2%
कभी बाहर नहीं होतीं	128	25.6%	84.8%
कोई नहीं	76	15.2%	100%
कुल	**500**	**100%**	**100%**

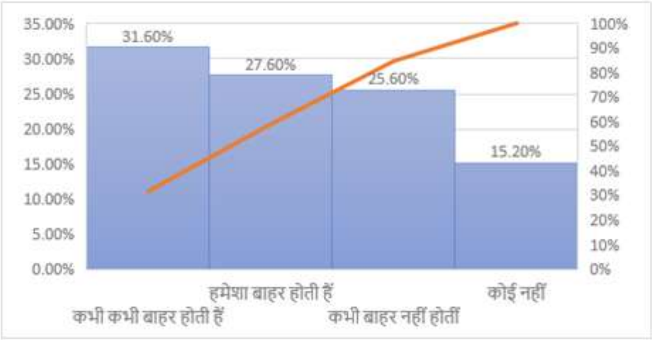

सांख्यिकीय चित्र 4.7: क्या पारंपरिक मान्यताओं के कारण कुछ पारिवारिक निर्णयों से महिलाएँ बाहर होती हैं?
27.6 प्रतिशत महिलाएं पूरी तरह से सहमत हैं कि पारंपरिक मान्यताओं के कारण महिलाएं पारिवारिक निर्णयों से बाहर होती हैं 31.6 प्रतिशत कभी-कभी बाहर होती हैं, 25.6 प्रतिशत कभी बाहर नहीं होतीं, और 15.2 प्रतिशत का कहना है कि वे कभी बाहर नहीं होतीं। यह आंकड़े दर्शाते हैं कि पारंपरिक मान्यताएं महिलाओं की पारिवारिक निर्णयों में भागीदारी को प्रभावित करती हैं।

तालिका 4.8: क्या महिलाओं के पास स्वतंत्र निर्णय लेने के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं होते?

प्रतिक्रियाएँ	आवृत्ति	प्रतिशत	कुल प्रतिशत
पूरी तरह से सहमत	145	29.0%	29.0%
सहमत	153	30.6%	59.6%
नपे-तुले	115	23.0%	82.6%
असहमत	65	13.0%	95.6%
पूरी तरह से असहमत	22	4.4%	100%
कुल	500	100%	100%

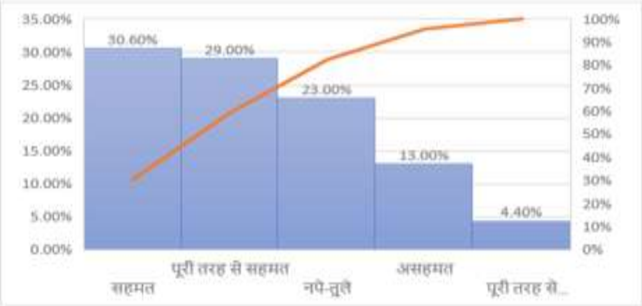

सांख्यिकीय चित्र 4.8:' क्या महिलाओं के पास स्वतंत्र निर्णय लेने के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं होते?
29 प्रतिशत महिलाएं पूरी तरह से सहमत हैं कि उन्हें निर्णय लेने के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं मिलते, 30.6 प्रतिशत सहमत हैं, 23 प्रतिशत महिलाएं निष्कलंक हैं, और 13 प्रतिशत महिलाएं असहमत हैं। 4.4 प्रतिशत महिलाएं पूरी तरह से असहमत हैं। यह दर्शाता है कि महिलाओं के पास निर्णय लेने के लिए संसाधनों की कमी महत्वपूर्ण चुनौती हो सकती है, विशेषकर जब आर्थिक और शैक्षिक संसाधन सीमित होते हैं।

तालिका 4.9: क्या आजकल महिलाओं को निर्णय लेने के अधिक अवसर मिल रहे हैं पहले के मुकाबले?

प्रतिक्रियाएँ	आवृत्ति	प्रतिशत	कुल प्रतिशत
पूरी तरह से सहमत	123	24.6%	24.6%
सहमत	187	37.4%	62.0%
नपे-तुले	105	21.0%	83.0%
असहमत	55	11.0%	94.0%
पूरी तरह से असहमत	30	6.0%	100%
कुल	500	100%	100%

International Journal of Enhanced Research in Educational Development (IJERED)
ISSN: 2320-8708, Volume 14, Issue 2, March-April

सांख्यिकीय चित्र 4.9: क्या आजकल महिलाओं को निर्णय लेने के अधिक अवसर मिल रहे हैं पहले के मुकाबले?
24.6 प्रतिशत महिलाओं ने पूरी तरह से सहमति व्यक्त की जबकि 37.4 प्रतिशत ने सहमति व्यक्त की कि आजकल महिलाओं को अधिक अवसर मिल रहे हैं। 21 प्रतिशत महिलाएं निष्कलंक रहीं, और 11 प्रतिशत ने असहमत व्यक्त किया। केवल 6 प्रतिशत महिलाएं पूरी तरह से असहमत हैं। इस आंकड़े से यह स्पष्ट होता है कि अधिकतर महिलाएं मानती हैं कि उन्हें निर्णय लेने के अधिक अवसर मिल रहे हैं।

तालिका 4.10: क्या पुरुष प्रधान राजनीतिक संरचनाएँ महिलाओं के निर्णय लेने की भूमिका पर प्रभाव डालती हैं?

प्रतिक्रियाएँ	आवृत्ति	प्रतिशत	कुल प्रतिशत
पूरी तरह से प्रभाव डालती हैं	163	32.6%	32.6%
कुछ हद तक प्रभाव डालती हैं	157	31.4%	64.0%
कोई प्रभाव नहीं	101	20.2%	84.2%
प्रभाव नहीं डालती हैं	79	15.8%	100%
कुल	**500**	**100%**	**100%**

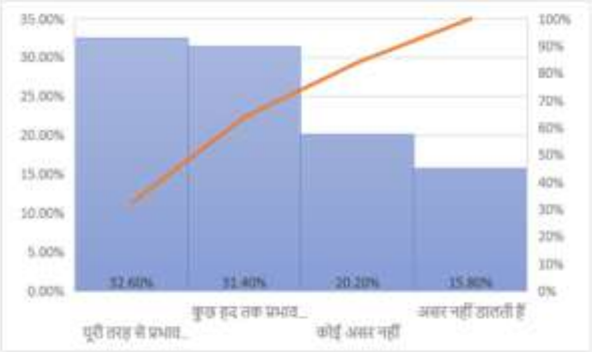

सांख्यिकीय चित्र 4.10: क्या पुरुष प्रधान राजनीतिक संरचनाएँ महिलाओं के निर्णय लेने की भूमिका पर प्रभाव डालती हैं?
32.6 प्रतिशत महिलाएं मानती हैं कि पुरुष प्रधान राजनीतिक संरचनाएं पूरी तरह से प्रभाव डालती हैं जबकि 31.4 प्रतिशत का कहना है कि इसका कुछ हद तक प्रभाव है। 20.2 प्रतिशत महिलाएं मानती हैं कि इसका कोई प्रभाव नहीं है और 15.8 प्रतिशत महिलाएं इसके प्रभाव से असहमत हैं। यह दिखाता है कि अधिकांश महिलाओं का मानना है कि राजनीतिक संरचनाएं उनके निर्णय लेने की क्षमता पर प्रभाव डालती हैं।

तालिका 4.11: क्या महिलाओं के सक्षमताकरण कार्यक्रमों या नीतियों तक पहुँच है?

प्रतिक्रियाएँ	आवृत्ति	प्रतिशत	कुल प्रतिशत
नियमित रूप से पहुँच	94	18.8%	18.8%
कभी कभी पहुँच	145	29.0%	47.8%
कोई पहुँच नहीं	261	52.2%	100%
कुल	**500**	**100%**	**100%**

सांख्यिकीय चित्र 4.11: क्या महिलाओं के सक्षमताकरण कार्यक्रमों या नीतियों तक पहुँच है?
18.8 प्रतिशत महिलाएं नियमित रूप से पहुंच प्राप्त करती हैं जबकि 29 प्रतिशत महिलाएं कभी-कभी पहुंच प्राप्त करती हैं। 52.2 प्रतिशत महिलाएं कहती हैं कि उन्हें इन कार्यक्रमों या नीतियों तक कोई पहुंच नहीं मिलती। इस तालिका से यह स्पष्ट होता है कि महिलाओं की एक बड़ी संख्या को सक्षमताकरण कार्यक्रमों का लाभ नहीं मिल पा रहा है।

परिकल्पनाः परिवार की संरचना और प्रकार्य महिलाओं की पारिवारिक स्थिति तथा निर्णय-क्षमता के आकलन में कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाते।

लक्ष्यः यह परीक्षण करना कि क्या परिवार की संरचना और प्रकार्य महिलाओं की पारिवारिक स्थिति और निर्णय-क्षमता में सहसंबंधित हैं।

तालिका 4.12: परिवार की संरचना एवं प्रकार्य का सहसंबंध

चर	सहसंबंध	प्रतिक्रिया
परिवार की संरचना	0.71	सकारात्मक सहसंबंध
परिवार का प्रकार्य	0.65	सकारात्मक सहसंबंध

तालिका 4.13: प्रतिगमन विश्लेषण - परिवार की संरचना व प्रकार्य का प्रभाव

स्वतंत्र चर	निर्भर चर	बिटा	पी -मान
परिवार की संरचना	महिलाओं की पारिवारिक स्थिति	0.67	0.03 (महत्वपूर्ण)
परिवार का प्रकार्य	महिलाओं की निर्णय-क्षमता	0.62	0.02 (महत्वपूर्ण)

इस परिकल्पना में यह जाँचा गया कि परिवार की संरचना और प्रकार्य महिलाओं की पारिवारिक स्थिति और निर्णय-क्षमता में कितना प्रभाव डालते हैं। सह-संबंध विश्लेषण ने यह पाया कि परिवार की संरचना (आर = 0.71) और परिवार का प्रकार्य (आर = 0.65) महिलाओं की पारिवारिक स्थिति और निर्णय-क्षमता से मजबूत सहसंबंध रखते हैं। प्रतिगमन विश्लेषण में यह भी सिद्ध हुआ कि परिवार की संरचना और प्रकार्य महिलाओं की पारिवारिक स्थिति और निर्णय-क्षमता पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालते हैं क्योंकि बिटा मान 0.67 और 0.62 हैं और पी -मान 0.03 और 0.02 (महत्वपूर्ण) हैं।

निष्कर्ष और सारांश

सामाजिक और सांस्कृतिक बाधाएँ

- सामाजिक मान्यताएँः समाज की पारंपरिक मान्यताएँ महिलाओं के निर्णय लेने की क्षमता को रोकती हैं। 56 प्रतिशत उत्तरदाता मानते हैं कि सामाजिक मान्यताएँ महिलाओं की निर्णय-निर्माण प्रक्रिया में बाधा डालती हैं। केवल 6.2 प्रतिशत ने यह कहा कि इन्हें कोई प्रभाव नहीं पड़ता।
- संसाधनों की कमीः 55.4 प्रतिशत महिलाओं ने माना कि संसाधनों की कमी उनके पारिवारिक निर्णयों में भागीदारी को सीमित करती है। केवल 5.4 प्रतिशत महिलाओं ने यह माना कि संसाधनों की कोई कमी नहीं है।
- पितृसत्तात्मक विचारधाराः 56.2 प्रतिशत उत्तरदाता मानते हैं कि पितृसत्तात्मक विचारधारा महिलाओं की निर्णय-निर्माण क्षमता को रोकती है, जबकि 7.6 प्रतिशत ने इसे प्रभावहीन माना।

- कानूनी बाधाएँः 54.6 प्रतिशत महिलाएँ मानती हैं कि कानूनी बाधाएँ उनके निर्णय-निर्माण में समान रूप से भाग लेने में रुकावट डालती हैं। 30.6 प्रतिशत महिलाओं का कहना है कि कोई कानूनी रोक नहीं है।
- पारिवारिक समर्थन की कमीः 56.4 प्रतिशत महिलाएँ मानती हैं कि उनके परिवार उन्हें महत्वपूर्ण निर्णयों में भाग लेने के लिए समर्थन नहीं करते। केवल 16 प्रतिशत महिलाएँ मानती हैं कि परिवार उनका समर्थन करता है।

आर्थिक और शैक्षिक बाधाएँ

- ग्रामीण क्षेत्रों में भेदभावः 59.8 प्रतिशत महिलाएँ मानती हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को शहरी क्षेत्रों की तुलना में अधिक भेदभाव का सामना करना पड़ता है। यह महिलाओं के सामाजिक सक्षमताकरण में एक बड़ा अवरोध है।
- पारंपरिक मान्यताओं के कारण निर्णयों से बाहर रखनाः 59.2 प्रतिशत महिलाएँ कहती हैं कि पारंपरिक मान्यताएँ उन्हें पारिवारिक निर्णयों से बाहर रखती हैं। 15.2 प्रतिशत महिलाएँ मानती हैं कि उन्हें कभी बाहर नहीं रखा जाता।
- निर्णय लेने के लिए संसाधनों की कमीः 59.6 प्रतिशत महिलाएँ मानती हैं कि उनके पास स्वतंत्र निर्णय लेने के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं होते। केवल 4.4 प्रतिशत महिलाओं ने इसे पूरी तरह से असहमति में रखा।
- निर्णय लेने के अवसर में वृद्धिः 62 प्रतिशत महिलाएँ मानती हैं कि पहले के मुकाबले आजकल महिलाओं को निर्णय लेने के अधिक अवसर मिल रहे हैं हालांकि 6 प्रतिशत महिलाएँ इसे पूरी तरह से असहमत मानती हैं।
- राजनीतिक निर्णयों में भागीदारीः 64 प्रतिशत महिलाएँ मानती हैं कि उन्हें राजनीतिक निर्णयों में भागीदारी के लिए पर्याप्त समर्थन नहीं मिलता। 4 प्रतिशत महिलाओं का कहना है कि उन्हें कोई असहमति नहीं है।

इस शोध कार्य में महिलाओं की निर्णय-निर्माण क्षमता में आने वाली प्रमुख बाधाओं का विश्लेषण किया गया। इन बाधाओं में सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और कानूनी कारक शामिल हैं जो महिलाओं के सक्षमताकरण और उनके निर्णय-निर्माण में भागीदारी को प्रभावित करते हैं। इन अवरोधों को दूर करने के लिए आवश्यक है कि नीतिगत सुधार और समावेशी कार्यक्रमों को लागू किया जाए ताकि महिलाओं को परिवार और समुदाय के महत्वपूर्ण निर्णयों में प्रभावी भागीदारी मिल सके। लैंगिक समानता और महिलाओं के अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए इन बाधाओं के समाधान के लिए ठोस कदम उठाए जाने चाहिए।

ग्रंथ सूची

1. अकोस्टा, एम., वैन वेसल, एम., वैन बोमेल, एस., एम्पायर, ई. एल., ट्राइमन, जे., जैसोग्रे, एल., और फींड्ट, पी. एच. (2020). 'जॉइंट' फैसला लेने का क्या मतलब है? खेती में घर के अंदर फैसले लेने की समझः पॉलिसी और प्रैक्टिस के लिए मतलब। जर्नल ऑफ डेवलपमेंट स्टडीज, 56(6), 1210-1229.
2. अख्तर, एस., मुख्यद, एस., यूसुफ, एच., जफर, ए., और रजा, क्यू. ए. (2018). दक्षिणी पंजाब (पाकिस्तान) के ग्रामीण इलाकों में सामाजिक और खेती से जुड़े फैसले लेने में महिलाओं की भूमिका। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ ह्यूमैनिटीज एंड सामाजिक साइंस, 5(5), 34-38.
3. अबरार-उल-हक, एम., जाली, एम. आर. एम., और इस्लाम, जी. एम. एन. (2017). पाकिस्तान की ग्रामीण महिलाओं में एम्पावरमेंट के सोर्स के तौर पर फैसले लेने की क्षमता। ग्लोबल सामाजिक वेलफेयर, 4(3), 117-125.
4. अली, एम. ए., और कामराजू, एम. (2023). ग्रामीण डेवलपमेंट योजना में महिलाओं की भूमिका. एएसईएएन जर्नल ऑफ कम्युनिटी सर्विस एंड एजुकेशन, 2(1), 67-84.
5. कोचर, ए., नागभूषण, सी., सरकार, आर., शाह, आर., और सिंह, जी. (2022). वित्तीय एक्सेस और घरेलू फैसलों में महिलाओं की भूमिकाः भारत के नेशनल रूरल लाइवलीहुड प्रोजेक्ट से मिले अनुभव। जर्नल ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, 155, 102821.
6. झेंग, एक्स., और लू, एच. (2021). क्या आईसीटी पीछे छूटी महिलाओं की घर के फैसले लेने की ताकत को बदलता है? चीन का एक मामला। टेक्नोलॉजिकल फोरकास्टिंग एंड सामाजिक चेंज, 166, 120604.
7. टाडेले, ए., टेस्फे, ए., और केबेडे, ए. (2019). इथियोपिया के दक्षिण-पश्चिम में मेट्टू ग्रामीण जिले में शादीशुदा महिलाओं में प्रजनन स्वास्थ्य और अधिकारों के बारे में फैसले लेने की ताकत पर प्रभाव डालने वाले फैक्टर। रिप्रोडक्टिव हेल्थ, 16(1), 155.
8. टेसेमा, के. एफ., यिहुने, एम., बोटी, एन., और हैलीमरियम, जेड. (2025). ग्रामीण साउथ इथियोपिया में बच्चों को खिलाने के बारे में महिलाओं के फैसले पर प्रभाव डालने वाली सामाजिक-सांस्कृतिक रुकावटेंः देखभाल करने वालों और खास लोगों का नजरिया। एसएजीई ओपन, 15(2), 21582440251339887.
9. डिक्सन, आर. बी. (2013). ग्रामीण महिलाओं की भूमिकाएँः महिलाओं का अकेलापन, इकोनॉमिक प्रोडक्शन, और रिप्रोडक्टिव चॉइस। पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट में (पेज 290-321)। आरएफएफ प्रेस।
10. प्रशांति, बी., और देवी, एम. एस. (2019). ग्रामीण महिलाओं के चुने हुए जीवन स्किल्स लेवल्स (फैसले लेना, प्रॉब्लम सॉल्विंग और कम्युनिकेशन स्किल्स) पर इंटरवेंशन के प्रभाव पर एक स्टडी। द फार्मा इनोवेशन जर्नल, 8(7), 362-364.
11. बेस्चर-डोनेली, एल., और स्मिथ, एल. डब्ल्यू. (2019). ग्रामीण महिलाओं की बदलती भूमिकाएं और स्थिति. ग्रामीण समाज में परिवार में (पेज 167-185). रूटलेज.
12. ली, जेड. (2022). क्या परिवार के फैसले लेने की ताकत महिलाओं की खुशी बढ़ाती है? परिवार मुद्दों का जर्नल, 43(8), 2016-2039।

13. लेकाउटेरे, ई., और चू, एल. (2024). घर के अंदर फैसले लेने की प्रक्रिया में बदलाव करके महिलाओं के सक्षमताकरण को समर्थन देनाः ग्रामीण दक्षिण-पश्चिम तंजानिया में एक क्षेत्रीय प्रयोग का मिश्रित-मेथड विश्लेषण। विकास नीति समीक्षा, 42(3), म12758।
14. वैन ट्रुओंगा, डी., गियांगब, एन. डी. एच., लैंब, एल. टी., और फाम, एन. टी. बी. टी. (2020). ग्रामीण इलाकों में घरेलू फैसले लेने में लैंगिक की भूमिका। प्रबंधन विज्ञान पत्र, 10, 2583-2588।
15. वादेई, बी., वादेई, के. ए., और बोनुएडी, आई. (2025). महिलाओं के काम और घरेलू क्षमता के डायनेमिक्स के बीच संबंधों की फिर से जांचः ग्रामीण और शहरी घाना से मिली जानकारी। मानव भूगोल, 19427786251333094।
16. विलियम्स, एल. बी. (2019). विकास, जनसांख्यिकी, और परिवार निर्णय-निर्माणः ग्रामीण जावा में महिलाओं की स्थिति। रूटलेज।
17. शुक्ला, पी., कुमारी, ए., लाल, एस. पी., और सुष्मिता, के. (2025). खेती-बाड़ी के विभिन्न कार्यों में खेतिहर महिलाओं के बीच फैसले लेने के प्रेरकः अग्रिम-चरण लॉजिस्टिक रिग्रेशन मॉडल तकनीक। भारतीय शोध पत्रिका विस्तार शिक्षा, 25, 18-23।
18. सोह वेंडा, बी. डी., फॉन, डी. ई., मोलुआ, ई. एल., और लोंगंग, एस. जी. (2024). महिलाएं, आय का उपयोग और पोषण गुणवत्ताः कैमरून में ग्रामीण परिवारों में महिलाओं के फैसले लेने का प्रभाव। कृषि और खाद्य सुरक्षा, 13(1), 29।